जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोन:- 256906, 256907, फैक्स:- 01562-256908 वर्ष: 17 संख्या: 262 प्रभात चूरू, रविवार 18 जनवरी, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

मुम्बई में "रिज़ॉर्ट" राजनीति की वापसी

एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को ताज होटल में शिफ्ट किया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। मुंबई में स्थानीय बीएमसी चुनावों के बाद अब राजनीतिक जोड़-तोड़ और रस्साकशी शुरू हो गई है। भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल शिंदे गुट की शिवसेना, जिसने 29 सीटें जीती हैं, अब अपनी ताकत दिखा रही है।

एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को ताज होटल में ठहरा दिया है और "रिसॉर्ट पॉलिटिक्स" एक बार फिर सक्रिय हो गई है। शिंदे, भाजपा का मेयर बनाने के बदले "मुँह-माँगी कीमत" वसूलना चाहते हैं।

रिकॉर्ड के लिए बता दें कि शिंदे मेयर पद के लिए ढाई-ढाई साल के रोटेशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस मांग को मानने वाली नहीं है।

लेकिन शिंदे को जो मिलने की संभावना है, वह है स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की कमान, जो कि मेयर पद के बाद, धन-संपन्न बीएमसी की सबसे ताकतवर समिति मानी जाती है।

- भाजपा के 88 पार्षद जीते हैं, पर, बीएमसी में बहुमत पार करने के लिए 117 सीटों पर जीतना जरुरी है। अतः शिंदे ग्रुप द्वारा जीती गई 29 सीटें जरुरी हैं, भाजपा को अपना मेयर बनाने के लिए।
- इसलिए, शिंदे भाजपा से भारी सौदेबाजी करने के मूड में हैं।
- शिंदे का पहला प्रस्ताव है, पहले ढाई साल के लिए उसके नेता को मेयर बनाया चाहिए, जो आधे कार्यकाल के पश्चात मेयर पद छोड़ देगा, भाजपा के लिए।
- शिंदे जानते हैं कि इस प्रस्ताव पर भाजपा कभी राजी नहीं होगी। अतः ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे को बीएमसी में स्टैण्डिंग कमेटी के अध्यक्ष का पद दिया जाए। यह पद मेयर के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद माना बृहन्मुम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में।
- शिंदे का यह भी प्रस्ताव है कि यह बाल ठाकरे की विरासत है कि बीएमसी पर शिवसेना का मेयर ही होता है। अतः शिवसेना (शिंदे ग्रुप) को मेयर पद मिलना ही चाहिए।
- जैसा कि विदित ही है, कांग्रेस को बीएमसी चुनाव में कुल चार प्रतिशत वोट मिले हैं, इतने कम वोट अब तक कांग्रेस के कभी नहीं मिले हैं। कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा यह आरोप लगा रहा है कि इतने कम वोट मिलने का सबसे बड़ा कारण है, मुम्बई के प्रभारी द्वारा कांग्रेस के टिकट बेचना।

विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र में भाजपा का उभार कई राजनीतिक दलों के गलत फैसलों और सही समय पर सही गठबंधन न करने का नतीजा है। उनका मानना है कि कांग्रेस को शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहिए था और मुंबई में टिकटों की बिक्री नहीं करनी चाहिए थी, जैसा कि कांग्रेस के मुंबई प्रभारी ने किया।

कांग्रेस को केवल 4 प्रतिशत वोट मिले हैं, जो पार्टी का अब तक का सबसे कम वोट-प्रतिशत है।

'प.बंगाल में मुम्बई जैसी जीत मिलेगी'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में कहा कि भारत की जेन ज़ी भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करती है। उन्होंने हाल ही में मुंबई में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का हवाला देते हुए भरोसा जताया कि बंगाल के मतदाता भी इस बार भाजपा को चुनेंगे।

मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस जीत की पुनरावृत्ति बंगाल में भी होगी।

- प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालदा की एक जनसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल की युवा पीढ़ी को भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा है।

बंगाल में राज्य विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिंदे सेना को ठाणे में अपने आप में बहुमत मिला है

शिंदे ग्रुप को 70 सीटों पर ठाणे में विजय हासिल हुई है, जबकि, बहुमत पार करने के लिए कुल 66 सीटों पर जीत जरुरी होती है, 131 सदस्यीय ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। पूरे महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में अभी मतगणना जारी है, लेकिन 25 वर्षों बाद ठाकरे परिवार की मुंबई की नगर-सत्ता पर पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला गठबंधन बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) चुनाव में जीत की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है।

भाजपा की नज़र मुंबई के मेयर पद पर है। लेकिन, शिवसेना के बिना भाजपा बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकती। सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से मेयर बनाए जाने के लिए दबाव बना सकते हैं।

शुक्रवार के अंत तक, भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना देश के सबसे अमीर नगर निकाय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पर नियंत्रण पाने की स्थिति में दिखीं, जिसे वे ठाकरे परिवार से छीनने जा रही हैं। ठाकरे परिवार 2022 तक लगातार कम से कम 25 वर्षों तक बीएमसी में मेयर पद पर काबिज रहा था।

- ठाणे में शिंदे सेना की इस जीत से भाजपा ने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि, ठाणे में अपने प्रत्याशी को मेयर बनाने के बाद शिंदे अब बीएमसी में भी अपनी पार्टी के आदमी को ही मेयर बनाने पर ज्यादा जोर नहीं देंगे।
- और, अभी सार्वजनिक रूप से शिंदे बीएमसी के मेयर पद की जो मांग कर रहे हैं, इसका शायद कारण यह है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को यह "इम्प्रेशन" नहीं देना चाहते कि बिना कुछ संघर्ष किये ही उन्होंने बीएमसी का मेयर पद भाजपा को सौंप दिया।

कुल आंकड़ों पर नज़र डालें तो 227 सीटों वाली बीएमसी में 117 सीटें गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है, जो देखने में पर्याप्त लगता है, लेकिन कहानी में मोड़ भी आ सकता है।

आधी रात तक भाजपा 88 वार्डों में जीत या बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ किसी असंभव गठजोड़ को छोड़ देने की स्थिति में, ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है, जिसमें भाजपा शिंदे की शिवसेना (जो 29 वार्डों में आगे थी) के समर्थन के बिना निगम चला सके।

इस अंकगणित और "किंगमेकर"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आईसीसी के भारतीय अफसर को वीज़ा नहीं दिया बांग्लादेश ने

बांग्लादेश और आईसीसी के बीच टी-20 विश्व कप का विवाद गहराता जा रहा है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 17 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के बीच चल रही उच्चस्तरीय वार्ताओं का 'अंतिम दौर' एक बड़ी लॉजिस्टिक समस्या के साथ शुरू हुआ। प्रस्तावित दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वीज़ा संबंधी जटिलताओं के कारण आधा रह गया। आईसीसी के भ्रष्टाचार-रोधी एवं सुरक्षा प्रमुख एंड्रयू एफग्रेव 17 जनवरी को अकेले ढाका पहुंचे, ताकि आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर बने गतिरोध पर बातचीत की जा सके। वहीं, आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता को समय पर वीज़ा न मिलने के कारण पीछे ही रुकना पड़ा।

इस दौरे को क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय शासी संस्था की ओर से एक अंतिम प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, ताकि 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट पर मंडरा रहे कूटनीतिक और खेल संबंधी संकट को सुलझाया जा सके।

- आईसीसी (इंटरनैशनल क्रिकेट काउन्सिल) की दो सदस्यीय टीम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ वार्ता के लिए ढाका जाने वाली थी, पर, बांग्लादेश ने टीम के भारतीय सदस्य संजोग गुप्ता को वीज़ा नहीं दिया जो आईसीसी के सीईओ हैं।
- इसके बाद संजोग गुप्ता को रुकना पड़ा और एन्ड्रू एफग्रेव अकेले ही ढाका गए।
- इस यात्रा को गतिरोध दूर करने का आखिरी प्रयास बताया जा रहा था। ज्ञातव्य है कि 7 फरवरी से टी-20 वर्ल्ड कप शुरु हो रहा है।

विवाद की जड़ में बांग्लादेश सरकार और बीसीबी द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताएं हैं। बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से शीर्ष क्रिकेट संस्था से अनुरोध किया है कि मौजूदा राजनीतिक हालात और अपने खिलाड़ियों व स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए, उनके निर्धारित ग्रुप-स्टेज मुकाबलों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित किया जाए।

सहकर्मी की अनुपस्थिति में, अब बातचीत का पूरा बोझ केवल एफग्रेव पर है। अंतरराष्ट्रीय खेल सुरक्षा में व्यापक अनुभव रखने वाले पूर्व ब्रिटिश पुलिस अधिकारी एफग्रेव से अपेक्षा है कि वे एक विस्तृत सुरक्षा योजना पेश करेंगे, जिससे बांग्लादेशी अधिकारियों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैचों के दौरान उनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिगो पर 22 करोड़ रु. का जुर्माना

नयी दिल्ली, 17 जनवरी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो संकट की उड़ानों में व्यवधान की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर उस पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, और एक अधिकारी को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है। नियामक ने एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को भी इस मामले में आगाह किया है।

- दिसंबर के पहले सप्ताह में आए संकट के मसले पर डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यह जुर्माना लगाया और एयरलाइन के सी ई ओ को हटाने का भी निर्देश दिया।

गत 03 दिसंबर से 05 दिसंबर के बीच इंडिगो की 2,507 उड़ानें रद्द रही थीं और 1,852 उड़ानों में देरी हुई थी। हालांकि बड़े पैमाने पर व्यवधान उसके बाद भी जारी रहा था, लेकिन डीजीसीए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान में क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी की वापसी अच्छा संकेत नहीं है भारत के लिए

ईरान का राज परिवार अपने पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जाना जाता रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 जनवरी। ईरान के निर्वासित युवराज रज़ा पहलवी, जो सरकार-विरोधी अशांति के बीच अपने पुराने साम्राज्य में संभावित वापसी की कोशिश कर रहे हैं, का कहना है कि उनके नेतृत्व में "लोकतांत्रिक ईरानी राज्य" भारत के साथ घनिष्ठ और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहेगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और ऐतिहासिक रिश्तों का हवाला दिया।

वॉशिंगटन में आयोजित एक भीड़भाड़ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पहलवी ने कहा कि भारत और ईरान के संबंध बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और यह रिश्ता आधुनिक कूटनीति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा, "सांस्कृतिक रूप से यह रिश्ता वर्षों पुराना है" तथा आधुनिक इतिहास में भी दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं।

हालांकि, ईरान में पहलवी की संभावित वापसी भारत के लिए मिले-जुले संकेत प्रस्तुत करती है। एक ओर, जहाँ इससे प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के करीबी और पाकिस्तान-समर्थक ईरान का उभरना भारत के लिए जोखिम भी पैदा कर सकता है, खासतौर पर चाबहार बंदरगाह तक भारत की पहुंच को लेकर।

- रज़ा पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, 1941 से 1979 तक ईरान की सत्ता पर काबिज़ थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य, आर्थिक एवं कूटनीतिक संबंध विकसित किए थे तथा 1965 व 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया था और वे कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान के पक्ष में थे।
- युवराज रज़ा पहलवी ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए न केवल लोकतांत्रिक सुधारों की बात कही बल्कि भारत के साथ अच्छे संबंधों का समर्थन किया और कहा, दोनों देशों के सैंकड़ों सालों से नज़दीकी संबंध रहे हैं।
- रज़ा पहलवी का आगमन भारत पर मिला जुला प्रभाव डाल सकता है, दोनों देश में तकनीकी व आर्थिक संबंध बेहतर हो सकते हैं, पर, अमेरिका समर्थित व पाकिस्तानी रुझान वाला ईरान भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता और चाबहार पोर्ट तक भारत की पहुँच को प्रभावित कर सकता है।

ऐतिहासिक रूप से, रज़ा पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, जो 1941 से 1979 तक ईरान के अंतिम शाह थे, के शासनकाल में ईरानी राजशाही के पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध थे। ईरान पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक अहम बफर स्टेट मानता था।

शाह ने 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। उनके शासन में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान के रुख का जोरदार समर्थन किया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को आक्रामक ठहराया। यह रुख 1979 के बाद बनी इस्लामिक रिपब्लिक के अपेक्षाकृत तटस्थ रुख से बिल्कुल अलग था।

हालांकि रज़ा पहलवी लोकतांत्रिक सुधारों और सहयोग का वादा करते हैं, लेकिन उनकी वापसी ईरान को फिर से कश्मीर पर पाकिस्तान-समर्थक रुख की ओर ले जा सकती है।

पहलवी ने कहा कि एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या

ढाका, 17 जनवरी। बांग्लादेश के गाजीपुर जिले में शनिवार को एक हिंदू कारोबारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वह अपनी मिठाई की दुकान में काम करने वाले एक नाबालिग कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

- मृतक लिटन चंद्र घोष की मिठाई की दुकान थी और दुकान पर काम करने वाले लड़के को बचाने पर हमलावरों ने लिटन के सिर पर फावड़ा मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान 55 वर्षीय लिटन चंद्र घोष उर्फ काली के रूप में हुई है। वह बैशाखी स्वीटमीट एंड होटल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा के लिए अजीबोगरीब अपील की

हालांकि, यह भी सच है, ममता बनर्जी ने यह अपील, संविधान की सुरक्षा की मांग के छद्म रूप में की

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 17 जनवरी। एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) की जांच पर रोक से इनकार और स्थानीय पुलिस को ईडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे कार्रवाई न करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हुए नुकसान को झेल रहीं ममता बनर्जी ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश से संविधान की रक्षा का नाम लेते हुए खुद को सुरक्षा देने की मांग की।

ईडी द्वारा कंसल्टेंसी फर्म "आई पैक" के दफ्तरों पर की गई छापेमारी से जुड़े अपने आचरण को लेकर खुद को घिरा हुआ महसूस करते हुए ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय की उत्तर बंगाल पीठ के लिए बने नए अदालत भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आई थीं।

वे अपनी सुरक्षा की अपील सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कर रही थीं, जो अन्य विधि विशेषज्ञों के साथ इस समारोह में उपस्थित थे। यह एक विचित्र स्थिति थी, जिसमें अभियुक्त और कथित अपराधी स्वयं अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कानूनी संरक्षण मांग रहा था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता स्थित कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के दफ्तरों में जांच करने को लेकर ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राज्य की मुख्यमंत्री ने खुद कोलकाता में फर्म के मुख्यालय पर चल रही जांच के दौरान वहां से फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और मोबाइल फोन सहित, सारी महत्वपूर्ण सामग्री उठा ली थी।

ईडी करोड़ों रुपये के एक कोयला घोटाले की जांच कर रही थी, जिसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी के लीज क्षेत्रों में अवैध खनन शामिल था। बाद में इस धन को हवाला चैनलों के जरिए भेजा गया। ईडी ने इन जांचों के लिए आवश्यक सामग्री की चोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराने की मांग की थी।

- ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट की उत्तर बंगाल बैंच के लिए निर्मित न्यायालय भवन के उद्घाटन समारोह में अपने भाषण के दौरान यह मांग की।
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी इस समारोह में शरीक होने, दिल्ली से आए हुए थे तथा ममता बनर्जी की अपील को उन्होंने ध्यान से सुना।
- जैसा कि विदित ही है, ममता बनर्जी एक कंसलटैंट फर्म, आई-पैक के दफ्तर पर ईडी द्वारा की जा रही "रेड" के दौरान पुलिस के एक दस्ते के साथ वहाँ पहुँचकर कई सबूत की फाइलें, कागज़ात व कम्प्यूटरों आदि के अधिग्रहण कर अपने साथ ले गईं थीं।
- उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराकर मांग की थी कि ईडी की रेड को स्थगित कराया जाए तथा निर्देश जारी किए जाएं कि स्थानीय पुलिस के खिलाफ ईडी द्वारा जारी एफआईआर पर भी कुछ आगे कार्यवाही न की जाए।
- सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की दोनों मांगों को अस्वीकार कर ममता बनर्जी व पुलिस के दस्ते को नोटिस जारी किये थे।

ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोयला माफिया की अवैध गतिविधियों की जांच कर रही है, जो एक गंभीर आर्थिक अपराध है। इसमें मुख्यमंत्री का व्यवहार अभूतपूर्व था और उच्च स्तरीय आर्थिक अपराध की जांच से जुड़ी सामग्री की स्पष्ट चोरी के समान था। सामान्य परिस्थितियों में इस तरह के आचरण पर तुरंत गिरफ्तारी और अभियोजन होना चाहिए था।

ममता बनर्जी इस तरह का आचरण पहले भी कई बार कर चुकी हैं और किसी भी प्रकार के दंड के बचती रही हैं। लेकिन इस बार उनके खिलाफ जन असंतोष और कार्रवाई की मांग कहीं अधिक मजबूत है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

26 जनवरी से पहले आतंकी हमले का अलर्ट जारी

नई दिल्ली, 17 जनवरी। गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी) से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, खालिस्तानी आतंकवादी संगठन और

- इन्टेलिजैंस सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश तथा खालिस्तानी आतंकी समूह पंजाब के गैंगस्टर्स के सम्पर्क में है और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। पंजाब के ये गैंगस्टर्स हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में सक्रिय हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)